

तिरुवल्लुर, महाराष्ट्र के समर्थ रामदास आदि की रचनाओं का अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी सहित सभी भारतीय भाषाओं में हो। इसके लिए एक Center of Classical Studies स्थापित किया जाए और इसके चार Regional Centers बनाए जाएं, जिससे देश में विचारों का मौलिक और सहज प्रवाह हो।

यूरोप ने अपने सभी Classical texts को संरक्षित किया है। अनुवाद विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में किया गया है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें और Center for Classical Studies की स्थापना करें।

**Demand to ensure that MSP reach to the farmers by  
protecting them from middlemen**

**श्री हरनाथ सिंह यादव** (उत्तर प्रदेश): महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सदन के द्वारा एक अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, भारत सरकार ने आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगुना करने के लिए अनेक सार्थक प्रयास किए हैं। हम सभी जानते हैं कि "किसान सशक्त तो देश सशक्त", "किसान की जेब भारी तो देश की जेब भारी।"

महोदय, इस दिशा में सरकार ने किसानों को खरीफ की 14 फसलों का लागत से डेढ़ गुना मूल्य घोषित करके एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसका किसानों ने हृदय से स्वागत किया है।

परन्तु, मैं इससे सदन के द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि न्यूनतम घोषित मूल्य की जेब तक पहुंचे, इसके लिए सरकार को उचित समय पर कठोर और व्यापक कदम उठाने की जरूरत है।

मान्यवर, अभी डेढ़-दो माह पश्चात् फसलें मार्केट में आना प्रारम्भ हो जायेंगी, अतः सरकार को व्यापक व तत्काल सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करना अपेक्षित है, आवश्यक है।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि किसानों को सरकारी तंत्र और बिचौलियों के कुचक्र से बचाकर इस संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर वांछित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि किसानों को सरकार द्वारा न्यूनतम घोषित मूल्य हर दशा में मिल सके।

**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)**: श्री कैलाश सोनी। आप उसी का वाचन करिए, जो आपने यहां पर लिखकर दिया है।

**Demand to build and maintain the service and internal roads for cities  
along with main roads and over bridges**

**श्री कैलाश सोनी** (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सर्विस रोड्स की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि रोड्स निर्माण के मामले में सरकार का कार्य अत्यंत सराहनीय है। सारे देश में गुणवत्ता की रोड्स का निर्माण हो रहा है।

[श्री कैलाश सोनी]

समस्या विचलन मार्गों की है। सभी जगह जहां रोड्ज एवं ओवर ब्रिजों का निर्माण हो रहा है, वहां सर्विस रोड्ज (विचलन मार्गों) का निर्माण पहले होना चाहिए। साथ ही इनका रख-रखाव भी होता रहे, अन्यथा लोग कष्ट का अनुभव करते हैं।

इसके साथ ही बड़ी रोड्ज निर्माण होने के बाद तुरंत या साथ में नगरों के भीतर भी एप्रोच बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। इससे ज्यादा समय शहर के भीतर पहुंचने में लगता है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार को इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया):** श्री प्रताप सिंह बाजवा, अनुपस्थित। डा. किरोड़ी लाल मीणा, अनुपस्थित। श्रीमती कहकशां परवीन, अनुपस्थित। श्री अखिलेश प्रसाद सिंह।

#### **Demand to expedite the work of new AIIMS projects**

**श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार):** महोदय, आज देश के स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक है। सरकार ने वर्ष 2014 से 2017 के बीच में 13 नये "एम्स" के निर्माण की घोषणा की, लेकिन इनमें से 11 संस्थानों के निर्माण हेतु आबंटित राशि का 5 प्रतिशत से भी कम व्यय किया गया है तथा कुछ के लिए कैबिनेट की स्वीकृति लेना शेष है। जाहिर है कि इसके निर्माण तथा जनता सेवा में समर्पित होने में अभी कई और वर्ष लगेंगे। हाल ही में लोक सभा में स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह स्वीकार किया था कि वर्तमान में कार्यरत सभी छह "एम्स" के विभिन्न विभागों में 60 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। जो इस बात का संदेह पैदा करती है कि ऐसी सरकारी घोषणाएं धरातल पर वास्तविकता में दिखेंगी भी या नहीं?

महोदय, मैं बिहार से आता हूं और राज्य में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुका हूं तथा स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्बलस्था एवं गरीब जनता की पीड़ा को मैंने करीब से महसूस किया है। आज देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है। अतः मेरा आग्रह है कि नये "एम्स" स्थापित करने की दिशा में सरकार ठोस एवं त्वरित कार्रवाई करे, धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया):** प्रो. एम.वी. राजीव गौडा, अनुपस्थित। श्री रवि प्रकाश वर्मा, अनुपस्थित। श्री एस. मुत्तुकरुप्पन, अनुपस्थित। श्री डी. राजा, हो गया। श्री वि. विजयसाई रेड्डी।

#### **Request to implement recommendations of Kamalesh Chandra Committee for Gramin Dak Sevaks**

**SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh):** Sir, nearly 2.38 lakh Gramin Dak Sevaks are playing a pivotal role in the postal network, particularly in the rural areas. In fact, Gramin Dak Sevaks are the backbone of the Postal Department, as every postal service is incomplete without Gramin Dak Sevaks. It is no exaggeration when I say that Gramin Dak Sevaks cover 74 per cent of population of the country. They are working for